

136

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

हरिद्वार/देहरादून/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-2

देहरादून

दिनांक

09 अप्रैल, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु अनुदान संख्या-30 में आयोजनागत पक्ष की जिला योजनान्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं०-193/XXVII(I) दिनांक 30-3-2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल बालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के आयोजनागत पक्ष की जिला योजना में अनुसूचित जनजाति उपयोजना (ए.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत प्रथम चार माह (01 अप्रैल 2012 से 31 जुलाई 2012) हेतु कुल प्राविधनित बजट की धनराशि ₹0 2, 65,000.00 (रु० दो लाख पैंसठ हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

- 2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण एवम् व्यय किया जाएगा।
- 3) जिला योजना के अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय की सीमान्त एवं विभागीय प्रस्ताव के पूर्ण परीक्षण के उपरान्त उक्त धनराशि हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जनपद स्तर पर मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी जारी करेगी। जिला सेक्टर की योजना में ₹0 50 लाख की सीमा तक की स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर पर तथा उससे अधिक धनराशि वाली योजनाओं की स्वीकृति मण्डलायुक्त स्तर पर जारी की जायेगी।
- 4) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओं की सीमा तक ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग यदि अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अनाधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
- 5) सभी कार्यक्रमों/योजनाओं के मासिक/वार्षिक भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण स्वीकृत धनराशि का आहरण पूर्ण कर लिया जाय तथा उपरोक्त निर्धारित लक्ष्यों से शासन वित्त/नियोजन विभाग को अवगत कराया जाय।
- 6) जिला/मण्डल स्तर पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने, स्वीकृति/व्यय की प्रगति का संकलन, नियमित अनुश्रवण एवम् प्रगति विवरण संबंधी समस्त प्रक्रिया में अर्थ एवम् संख्या विभाग के जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारी तत्संबंधी पत्रावली सीधे जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे। राज्य स्तर पर निदेशक, अर्थ एवं संख्या के पृथक प्रकोष्ठ गठित कर जिला योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का संकलन करते हुए शासन को समयबद्ध उपलब्ध करायें।
- 7) जिला/मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यों का नियमित अनुश्रवण-मूल्यांकन एवम् स्थलीय सत्यापन के लिए टास्कफोर्स गठित कर सत्यापन कार्य जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त सुनिश्चित करायेंगे।
- 8) स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी०एम०-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/अपर सचिव (गन्ना विकास एवम् चीनी उद्योग विभाग), उत्तराखण्ड शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।